RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

# इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 08 SEPTEMBER TO 14 SEPTEMBER 2021 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 07 ■ अंक 2 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

लगातार सस्ता हो रहा है कच्चा तेल, यहां तीसरे दिन भी फेरबदल नहीं Page 2

अब सेल्फ सर्टिफाई कर सकेंगे जीएसटी रिटर्न फार्म Page 3

रुपया 18 पैसे टूटकर 73.60 रुपये प्रति डॉलर पर पहुंचा Page 4

editoria!

## क्या हम K- आकार की रिकवरी कर रहे है..?

विश्व में कोविड-19 के संक्रमण के बाद सभी देशों में आर्थिक व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन आए है। दुनिया का हर देश अर्थ व्यस्था में बदलाव देख रहा है। एक अर्थव्यवस्था के भीतर विभिन्न क्षेत्रों, उद्योगों और समूहों का आर्थिक प्रदर्शन हमेशा कुछ हद तक भिन्न होता है, लेकिन ख- आकार की रिकवरी में अर्थव्यवस्था के कुछ हिस्सों में मजबूत वृद्धि देखी जा सकती है जबकि अन्य में गिरावट जारी है। अन्य अक्षर के आकार के वर्णनकर्ताओं के विपरीत, जो बड़े समुच्चय पर ध्यान केंद्रित करते हैं, के-आकार की रिकवरी का वर्णन अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों में विभाजित डेटा के संदर्भ में किया जाता है। K- आकार की पुनर्प्राप्ति का अर्थ वास्तव में इस बात पर निर्भर करता है कि अर्थव्यवस्था में डेटा को कैसे अलग किया जाए।

### K- आकार की पुनर्प्राप्ति को समझना

'के-आकार' की वसूली शब्द 2020 में अमेरिका में तेज मंदी के मद्देनजर प्रमुखता से बढ़ गया, जो कि COVID-19 महामारी के साथ था, और इसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों, उद्योगों और लोगों के समूहों में असमान आर्थिक सुधार का वर्णन करने के लिए किया गया था। अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी और वसूली (एल-आकार, वी-आकार, यू-आकार, या डब्ल्यू-आकार) के अन्य अक्षर-आकार के वर्णनकर्ताओं के विपरीत, जो सकल घरेलू उत्पाद या कुल रोजगार जैसे अर्थव्यवस्था-व्यापी मैक्रोइकॉनॉमिक कुल चर के मार्ग का वर्णन करते हैं, ए के-आकार की वसूली विभिन्न अलग-अलग आर्थिक चर के मार्ग का वर्णन करती है, जैसे समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आय या विभिन्न उद्योगों में रोजगार, एक दूसरे के सापेक्ष।

### K- आकार की रिकवरी क्या है?

K- आकार की रिकवरी तब होती है, जब मंदी के बाद, अर्थव्यवस्था के अलग-अलग हिस्से अलग-अलग दरों, समय या परिमाण में ठीक हो जाते हैं। यह सभी क्षेत्रों, उद्योगों या लोगों के समूहों में एक समान, एकसमान वसूली के विपरीत है। के-आकार की रिकवरी अर्थव्यवस्था या व्यापक समाज की संरचना में बदलाव की ओर ले जाती है क्योंकि आर्थिक परिणाम और संबंध मंदी से पहले और बाद में मौलिक रूप से बदल जाते हैं। इस प्रकार की पुनर्प्राप्ति को K-आकार का कहा जाता है क्योंकि अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों का पथ जब एक साथ चार्ट किया जाता है, तो रोमन अक्षर 'K' की दो भुजाओं से मिलता-जुलता हो सकता है।

जबकि आर्थिक प्रदर्शन हमेशा अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों में भिन्न होता है, अर्थशास्त्री आम तौर पर अर्थव्यवस्था के सभी या अधिकांश क्षेत्रों में व्यापक रूप से सहसंबद्ध होने के लिए मंदी और वसूली के आर्थिक चक्रों को समझते हैं। 1 K- आकार की वसूली अलग बनाती है, जबकि अर्थव्यवस्था के कुछ हिस्से मंदी के तुरंत बाद अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो सकता है, अन्य सुस्त विकास में फंस सकते हैं या यहां तक कि गिरावट जारी रख सकते हैं। अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों के इस तरह के अलग-अलग प्रदर्शन का सामान्य आकार अक्षर 'के' के हथियारों जैसा दिखता है, यदि एक साथ चार्ट किया जाता है, जिसमें एक बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है।

इसका वास्तव में क्या मतलब है यह इस बात पर निर्भर करता है कि ख- आकार की प्रोफ़ाइल का सुझाव देने के लिए समग्र समष्टि आर्थिक डेटा को कैसे तोड़ा जाता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि कुछ उद्योग तेजी से उत्पादन में मजबूत वृद्धि की ओर लौटते हैं जबकि अन्य घटती गतिविधि देखते हैं, या यह कि कुछ प्रकार के परिसंपत्ति मूल्यों में वृद्धि होती है जबकि अन्य में गिरावट जारी रहती है, या यह कि समाज के कुछ वर्ग धन और आय में वृद्धि देखते हैं जबकि अन्य धन खो देते हैं और आय। इसका मतलब इन तीनों, या अन्य संभावनाओं से हो सकता है।

के-आकार की रिकवरी चलाने में कई अलग-अलग आर्थिक घटनाएं काम कर सकती हैं। सबसे पहले, के-आकार की वसूली अर्थशास्त्री जोसेफ शुम्पीटर द्वारा वर्णित अर्थव्यवस्था में रचनात्मक विनाश को प्रतिबिंबित कर सकती है, जो तब होता है जब नई प्रौद्योगिकियां और उद्योग मंदी के दौरान पुरानी प्रौद्योगिकियों और उद्योगों को प्रतिस्थापित करते हैं। दूसरा, यह सार्वजनिक नीति प्रतिक्रिया को प्रतिबिंबित कर सकता है मौद्रिक और राजकोषीय नीति के संदर्भ में एक मंदी, जो अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों को दूसरों की तुलना में अधिक लाभान्वित कर सकती है। अंत में, यह केवल उस अंतर प्रभाव को प्रतिबिंबित कर सकता है जो पहली बार में अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों पर प्रारंभिक मंदी का था, खासकर जब मंदी नकारात्मक वास्तविक आर्थिक झटके से मेल खाती है या ट्रिगर होती है जो अर्थव्यवस्था के विशिष्ट हिस्सों को प्रभावित करती है और स्थायी हो सकती है दूसरों की तुलना में उन पर अधिक प्रभाव पड़ता है। ध्यान दें कि ये तीनों परस्पर अनन्य नहीं हो सकते हैं; अन्य कारकों के साथ, तीनों दिए गए ख- आकार की रिकवरी में खेल सकते हैं।

एक के-आकार की रिकवरी वह है जिसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों का प्रदर्शन 'के' अक्षर की बाहों की तरह अलग हो जाता है।

## हाजिर मांग से कच्चा तेल वायदा कीमतों में तेजी

**नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क**

मजबूत हाजिर मांग के कारण कारोबारियों ने अपने सौदों के आकार को बढ़ाया जिससे वायदा कारोबार में बुधवार को कच्चा तेल की कीमत 40 रुपये की तेजी के साथ 5,053 रुपये प्रति बैरल हो गयी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में कच्चातेल के सितंबर डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 40 रुपये अथवा 0.8 प्रतिशत की तेजी के साथ 5,053 रुपये प्रति बैरल हो गई जिसमें 4,786 लॉट के लिए कारोबार हुआ। बाजार विश्लेषकों ने कहा कि कारोबारियों द्वारा अपने सौदों का आकार बढ़ाने से वायदा कारोबार में कच्चातेल कीमतों में तेजी आई। वैश्विक स्तर पर, न्यूयॉर्क में वेस्ट टैक्सास इंटरमीडिएट कच्चे तेल का दाम 0.51 प्रतिशत की तेजी के साथ 68.70 डालर प्रति बैरल हो गया जबकि वैश्विक मानक माने जाने वाले ब्रेंट क्रूड का दाम 0.38 प्रतिशत बढ़कर 71.96 डालर प्रति बैरल हो गया।

आम आदमी के लिए आई बड़ी खबर

## 1 जनवरी से बदल जाएगा आपके एटीएम और क्रेडिट कार्ड से जुड़ा नियम

**नई दिल्ली। एजेंसी**

**आरबीआई ने डेटा स्टोरेज से जुड़े टोकनाइजेशन के नियम जारी किए हैं। ग्राहक अपने कार्ड की डिटेल्स किसी थर्ड पार्टी ऐप जैसे- फूड डिलेवरी ऐप, कैब सेवा देने वाली कंपनियों की ऐप के साथ शेयर नहीं करनी होगी। पहले ऐसा करने से यूजर के कार्ड का डेटा इन वेबसाइट्स या ऐप पर सेव होता था, जिसके चोरी होने का डर लगा रहता है। टोकन सर्विस ग्राहकों की इच्छा पर निर्भर करेगी। इसे लेने के लिए उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं बनाया जा सकेगा और न ही बैंक/कार्ड जारी करने वाली कंपनियों द्वारा अनिवार्य रूप से इसे लागू किया जाएगा।**

### 1 जनवरी से अब कौन से नए नियम होंगे लागू

आरबीआई (ँघ) के नए नियमों के तहत 1 जनवरी, 2022 से कार्ड लेनदेन/पेमेंट में कार्ड जारीकर्ता बैंक या कार्ड नेटवर्क के अलावा कोई भी वास्तविक कार्ड डेटा स्टोरेज नहीं करेगा। इसमें पहले से स्टोर ऐसे किसी भी डेटा को फिल्टर किया जाएगा। हालांकि, ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग या सुलह मकसद के लिए, संस्थाएं सीमित डेटा स्टोर कर सकती हैं। वास्तविक कार्ड नंबर और कार्ड जारीकर्ता के नाम के आखिरी चार अंक तक के स्टोर की छूट होगी।

नियमों को मानने की जिम्मेदारी कार्ड नेटवर्क की होगी। CoFT मोबाइल, लैपटॉप, डेक्सटॉप स्मार्ट वॉच आदि के जरिए किए गए पेमेंट पर भी नियम लागू होगा। टोकन सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से जारी किए गए कार्ड के लिए ही टोकनाइजेशन की सुविधा की पेशकश की जाएगी। कार्ड डेटा को टोकननाइज करने और डी-टोकनाइज करने की क्षमता एक ही टोकन सर्विस प्रोवाइडर के साथ होगी। कार्ड डेटा का टोकनकरण ग्राहक की सहमति के साथ किया जाएगा। टोकनकरण के लिए AFA का भी इस्तेमाल किया जाएगा।

(शेष पृष्ठ 2 पर)

# लगातार सस्ता हो रहा है कच्चा तेल, यहां तीसरे दिन भी फेरबदल नहीं

**नई दिल्ली। एजेंसी**

**कच्चे तेल के सबसे बड़े निर्यातक सऊदी अरब ने आगामी अक्टूबर माह के लिए ऑफिसियल सेलिंग प्राइस में कटौती की घोषणा की है। इसके साथ ही इन दिनों अमेरिकी डॉलर मजबूत हो रहा है। मजबूत डॉलर की वजह से दूसरी करेंसी में कारोबार करने वालों के लिए इस समय क्रूड ऑयल खरीद कर होर्ड करना महंगा पड़ रहा है। इसलिए, क्रूड मार्केट में एक बार फिर से नरमी की धारणा बनी है। हालांकि, भारत में देखें तो यहां सरकारी तेल कंपनियों ने आज लगातार तीसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई फेरबदल नहीं किया। इससे तीन दिन पहले ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 15-15 पैसे की कमी की गई थी। दिल्ली के बाजार में बुधवार को इंडियन ऑयल के पंप पर पेट्रोल प्रति लीटर 101.19 रुपये पर टिका रहा। डीजल का दाम भी 88.62 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर है।**

### इस साल मई से जुलाई के बीच 11.52 रुपये महंगा हो चुका है पेट्रोल

इस साल की पहली तिमाही के दौरान कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चलने की वजह से बीते मार्च और अप्रैल में पेट्रोल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। इसलिए, उस दौरान कच्चा तेल महंगा होने के बाद भी पेट्रोल-डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। लेकिन, बीते चार मई से इसकी कीमतें खूब बढ़ी। कभी लगातार तो कभी ठहर कर, 42 दिनों में ही पेट्रोल 11.52 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। हालांकि, हरदीप सिंह पुरी के पेट्रोलियम मंत्री बनने के बाद बीते 18 जुलाई से इसके दाम स्थिर थे। रक्षा बंधन के दिन, इसके दाम में महज 20 पैसे की कमी की गई थी। उसके दो दिन बाद भी 15 पैसे की कमी हुई है। उसके बाद एक सितंबर और पांच सितंबर को इसके दाम फिर 15-15 पैसे घटे।

### पेट्रोल के मुकाबले थोड़ा सस्ता हुआ है डीजल

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल भले ही सस्ता बिक रहा हो, लेकिन यहां सरकारी तेल कंपनियां उस हिसाब से कीमतों में कमी नहीं कर रही हैं। वैसे भी डीजल महंगा ईंधन होने के बावजूद भारत में यह पेट्रोल के मुकाबले सस्ता बिकता है। इस साल के शुरूआती महीनों में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। उस दौरान 41 दिनों तक डीजल के दाम में कोई फेरदबल नहीं हुआ था। उस समय डीजल के दाम में अंतिम कमी बीते 15 अप्रैल को हुई थी। उस समय 14 पैसे की कमी हुई थी। लेकिन बीते 4 मई से इसमें जो ठहर-ठहर कर बढ़ोतरी हुई, उससे डीजल 9.08 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। उसके बाद बीते 16 जुलाई से इसके दाम में कोई फेरबदल नहीं हुआ था। बीते 18 अगस्त से 20 अगस्त तक इसकी कीमतों 20 पैसे प्रति लीटर की रोजाना कमी हुई है। इसके बाद रक्षा बंधन के दिन भी दाम में इतनी ही कमी हुई थी। उसके दो दिन बाद भी यह 15 पैसे सस्ता हुआ था। बीते एक सितंबर के 15 पैसे और पांच सितंबर के 15 पैसे की कमी को जोड़ लिया जाए तो पिछले एक पखवाड़े में अब तक डीजल 1.25 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो चुका है।

### कच्चे तेल के बाजार में नरमी

कच्चे तेल के सबसे बड़े निर्यातक सऊदी अरब ने आगामी अक्टूबर माह के लिए ऑफिसियल सेलिंग प्राइस (OSP) में कटौती की घोषणा की है। इसके साथ ही इन दिनों अमेरिकी डॉलर मजबूत हो रहा है। मजबूत डॉलर की वजह से दूसरी करेंसी में कारोबार करने वालों के लिए इस समय क्रूड ऑयल खरीद कर होर्ड करना महंगा पड़ रहा है। इसलिए, क्रूड मार्केट में एक बार फिर से नरमी की धारणा बनी है। अमेरिकी बाजार में मंगलवार को ब्रेंट क्रूड 0.53 डॉलर प्रति बैरल घट कर 71.69 डॉलर प्रति बैरल पर सेटल हुआ। डब्ल्यूटीआई क्रूड के दाम में भी 94 सेंट की कमी दर्ज की गई। कारोबार की समाप्ति पर यह 68.35 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ।

# विदेशी मुद्रा भंडार अब तक रिकार्ड 633 अरब डॉलर के पार

**नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क**

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 27 अगस्त को समाप्त सप्ताह में 16.7 अरब डॉलर बढ़कर अबतक के रिकॉर्ड 633.6 अरब डॉलर पर पहुंच गया जबकि इसके पिछले सप्ताह में यह 2.5 अरब डॉलर घटकर 616.9 अरब डॉलर रहा था। रिजर्व बैंक की ओर से जारी साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार, 27 अगस्त को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति 1.4 अरब डॉलर घटकर 571.5 अरब डॉलर पर रहा। हालांकि इस दौरान स्वर्ण भंडार 19.2 करोड़ डॉलर बढ़कर 37.44 अरब डॉलर पर पहुंच गया। अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के पास आरक्षित निधि 1.4 करोड़ डॉलर बढ़कर 5.1 अरब डॉलर हो गयी।

आलोच्य सप्ताह विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 17.9 अरब डॉलर बढ़कर अबतक के रिकॉर्ड 19.41 अरब डॉलर पर रहा। बीते सप्ताह देश के विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड बढ़ोतरी होने का प्रमुख कारण आईएमएफ द्वारा भारत को 17.86 अरब डॉलर एसडीआर का आवंटन करना है।

रिजर्व बैंक ने बताया कि आईएमएफ ने 23 अगस्त को 17.86 अरब डॉलर एसडीआर का आवंटन किया है, जिससे यह बढ़कर 19.41 अरब डॉलर हो गया है। आईएमएफ सदस्य देशों के बीच एसडीआर का आवंटन मौजूदा कोटा के अनुपात में करता है। आईएमएफ के निदेशक मंडल ने 2 अगस्त को सदस्य देशों के लिए 456 अरब एसडीआर के आवंटन को मंजूरी दी थी, जो 23 अगस्त से प्रभावी हो गया। इसमें भारत की हिस्सेदारी 12.57 अरब एसडीआर रही है।

# सरकार ने कोयला आधारित हाइड्रोजन उत्पादन पर दो समितियां गठित की

**नयी दिल्ली। एजेंसी**

केंद्र ने मंगलवार को कहा कि उसने कोयला आधारित हाइड्रोजन उत्पादन के लिये खाका तैयार करने को लेकर एक कार्यबल और एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। कोयला मंत्रालय ने एक बयान में कहा, " मंत्रालय ने मंगलवार को दो समितियों का गठन किया है। एक समिति कार्यक्रम की निगरानी के लिए है और दूसरी विशेषज्ञों की समिति है, जो मंत्रालय को मार्गदर्शन प्रदान करेगी।" मंत्रालय का यह कदम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पर्यावरण के अनुकूल स्वच्छ तरीके से हाइड्रोजन आधारित अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के एजेंडा के अनुरूप है। मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के दिन अपने संबोधन में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की थी। कोयला मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव विनोद कुमार तिवारी की अध्यक्षता में कार्यबल का गठन किया गया है। इसके लिये निर्धारित शर्तों में कोयला आधारित हाइड्रोजन उत्पादन और उपयोग को लेकर गतिविधियों की निगरानी तथा 'कोल गैसीफिकेशन मिशन' और नीति आयोग के साथ समन्वय करना शामिल है। बयान के अनुसार विशेषज्ञ समिति के लिये निर्धारित नियम एवं शर्तों में देश में विशेषज्ञों की पहचान करना और सदस्यों के रूप में चयन, हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी में प्रगति तथा हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी में चल रही अनुसंधान परियोजनाओं की समीक्षा करना शामिल है। विशेषज्ञ समिति द्वारा तीन महीने में रिपोर्ट दिये जाने की संभावना है।

# 1 जनवरी से बदल जाएगा आपके एटीएम और क्रेडिट कार्ड से जुड़ा नियम

**( प्रथम पृष्ठ का शेष )**

बैंकों के एटीएम से तय फ्री लिमिट से ज्यादा बार पैसा निकालने पर 1 जनवरी 2022 से नया चार्ज देना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को अगले साल से एटीएम के जरिये तय फ्री मंथली लिमिट से ज्यादा बार कैश निकालने या दूसरे लेन-देन करने को लेकर फीस बढ़ाने की परमिशन दे दी है। इसके तहत बैंक कस्टमर अगर फ्री निकासी या दूसरी सुविधाओं की तय लिमिट से ज्यादा बार लेन-देन करते हैं, तो उन्हें हर ट्रांजेक्शन पर 21 रुपये देने होंगे जो अभी 20 रुपये है। बैंकों के एटीएम से तय फ्री लिमिट से ज्यादा बार पैसा निकालने पर 1 जनवरी 2022 से नया चार्ज देना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को अगले साल से एटीएम के जरिये तय फ्री मंथली लिमिट से ज्यादा बार कैश निकालने या दूसरे लेन-देन करने को लेकर फीस बढ़ाने की परमिशन दे दी है। इसके तहत बैंक कस्टमर अगर फ्री निकासी या दूसरी सुविधाओं की तय लिमिट से ज्यादा बार लेन-देन करते हैं, तो उन्हें हर ट्रांजेक्शन पर 21 रुपये देने होंगे जो अभी 20 रुपये है।

# पेट्रोनेट की पेट्रोरसायन व्यवसाय में उतरने पर नजर ओडीशा में एलएनजी टर्मिनल लगाने की योजना

**नयी दिल्ली। एजेंसी**

देश में तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की सबसे बड़ी आयातक कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड गुजरात के दहेज में एक पेट्रोरसायन कारखाना लगाने की योजना बना रही है। कंपनी की गैस के कारोबार में होने वाले जोखिम को कम करने के लिये उंचे मार्जिन वाले पेट्रोरसायन कारोबार में उतरने पर नजर है। पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर ने यह कहा। पेट्रोनेट के दहेज और केरल के कोच्चि में प्राकृतिक गैस आयात करने के टर्मिनल हैं। कंपनी इसके साथ ही अब ओडिशा के गोपालपुर बंदरगाह में एक तैरने वाला समुद्री टर्मिनल बनाने की योजना बना रही है।

कपूर पेट्रोलियम सचिव के साथ ही पेट्रोनेट एलएनजी के चेयरमैन भी हैं। कंपनी की ताजा सालाना रिपोर्ट में कपूर ने कहा कि कंपनी अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को व्यापक बनाना चाहती है और उसमें बड़ा विविधीकरण लाने जा रही है। कंपनी दहेज टर्मिनल में एथेन..प्रोपेन आयात सुविधा विकसित करने की संभावनाओं को भी तलाश रही है। उन्होंने कहा कि पेट्रोनेट दहेज टर्मिनल में आयातित प्रोपेन पर आधारित एक पेट्रोरसायन परिसर भी स्थापित करने की योजना बना रही है। हालांकि, उन्होंने प्रस्तावित पेट्रोरसायन परिसर के बारे में ज्यादा विवरण नहीं दिया। पेट्रोरसायन में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल होता है और इसमें प्लास्टिक के लिये कच्चा माल, पैकेजिंग सामग्री और व्यक्तिगत देखभाल के उत्पाद तैयार होते हैं। पेट्रोनेट एलएनजी में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों इंडियन आयल कार्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन, गेल इंडिया और ओएनजीसी की कुल मिलाकर 50 प्रतिशत हिस्सेदारी है। चारों कंपनियां पेट्रोनेट के बोर्ड में शामिल है और पेटोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव इसके प्रमुख हैं।

# पेट्रोल-डीजल सहित अन्य पेट्रोलियम उत्पादों से सरकार की अप्रैल से जुलाई के बीच कमाई 48 प्रतिशत बढ़ी

**नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क**

सरकार का पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क संग्रह चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों में 48 प्रतिशत बढ़ गया है, और इस दौरान हासिल हुआ अतिरिक्त संग्रह पूरे वित्त वर्ष के दौरान तेल बॉन्ड देनदारी का तीन गुना है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत लेखा महानियंत्रक के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल-जुलाई 2021 के दौरान उत्पाद शुल्क संग्रह एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 67,895 करोड़ रुपये था। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था लागू होने के बाद उत्पाद शुल्क केवल पेट्रोल, डीजल, एटीएफ और प्राकृतिक गैस पर लगाया जाता है। इन उत्पादों को छोड़कर अन्य सभी वस्तुएं और सेवाएं जीएसटी के तहत हैं।

वित्त वर्ष 2021-22 के पहले चार महीनों (अप्रैल-जुलाई) में 32,492 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई, जो पूरे साल की तेल बॉन्ड देनदारी यानी 10,000 करोड़ रुपये का तीन गुना है। कांग्रेस की अगुवाई वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने पेट्रोलियम ईंधन पर सब्सिडी देने के लिए तेल बॉन्ड जारी किए थे। उद्योग सूत्रों ने कहा कि उत्पाद शुल्क संग्रह का बड़ा हिस्सा पेट्रोल और डीजल पर उपकर से आता है, और बिक्री में तेजी के साथ ही चालू वर्ष में संग्रह एक लाख करोड़ रुपये से अधिक बढ़ सकता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले दिनों कहा था कि पिछले कुछ वर्षों में इन ईंधनों पर दी गई भारी सब्सिडी के एवज में किये जा रहे भुगतान के कारण पेट्रोल, डीजल के दाम में कमी की ज्यादा गुंजाइश नहीं बची है। संप्रग सरकार में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और केरोसिन की बिक्री उनकी वास्तविक लागत से काफी कम दाम पर की गई थी। तब की सरकार ने इन ईंधनों की सस्ते दाम पर बिक्री के लिये कंपनियों को सीधे सब्सिडी देने के बजाय 1.34 लाख करोड़ रुपये के तेल बॉन्ड जारी किए थे। उस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर निकल गये थे।सरकार को चालू वित्त वर्ष 2021-22 में 10,000 करोड़ रुपये, 2023-24 में 31,150 करोड़ रुपये और उससे अगले साल में 52,860.17 करोड़ तथा 2025-26 में 36,913 करोड़ रुपये का भुगतान तेल बॉन्ड को लेकर करना है। सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क को पिछले साल 19.98 रुपये से बढ़ाकर 32.9 रुपये प्रति लीटर कर दिया। महामारी के दौरान जहां एक तरफ मांग काफी कम रह गई वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम गिर गये। ऐसे में सरकार ने उत्पाद शुल्क बढ़ाया।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्यमंत्री रामेश्वर तेली ने पिछले महीने संसद को बताया कि केन्द्र सरकार को पेट्रोल और डीजल से कर प्राप्ति 31 मार्च को समाप्त वर्ष में 88 प्रतिशत बढ़कर 3.35 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई जो कि एक साल पहले 1.78 लाख करोड़ रुपये रही थी। महामारी पूर्व वर्ष 2018-19 में यह 2.13 लाख करोड़ रुपये रही थी।

# अब सेल्फ सर्टिफाई कर सकेंगे जीएसटी रिटर्न फार्म

**कानपुर। एजेंसी**

जीएसटी रिटर्न दाखिल करते वक्त कंप्लायंस करना अब और आसान होगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की ओर से टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए निर्देश जारी किए है। उन्हें रिटर्न दाखिल करते वक्त सेल्फ सर्टिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट या कास्ट अकाउंटेंट से सर्टिफिकेशन नहीं कराना होगा। टैक्स पेयर खुद ही रिटर्न से जुड़े स्टेटमेंट्स को सेल्फ सर्टिफाई कर सकेंगे। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के जीएसटीआर- 9सी को दाखिल करते वक्त टैक्स पेयर्स को दो तरह की राहत मिलेगी। जिसके तहत उन्हें डाक्यूमेंटेशन में राहत मिलेगी। साथ ही उनका खर्च भी बचेगा। अभी यह राहत 5 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर वाले व्यापारी,कारोबारी को मिलेगी। आगे चल कर इस लिमिट को और कम भी किया जा सकता है।

### जीएसटीआर-9सी में राहत

फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से शुरू होने वाले जीएसटी रिटर्न फार्म-9सी के साथ टैक्सपेयर्स को उनके एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर के 5 करोड़ रुपए तक होने पर पहले रिकांसिलिएशन स्टेटमेंट दाखिल करना होता था,लेकिन अब जीएसटीआर-9सी के साथ रिकांसिलिएशन स्टेटमेंटट(समाधान विवरणा) की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ टैक्सपेयर्स पर से कंप्लायंस बर्डन कम होगा। मालूम हो कि कानपुर रीजन में 5 करोड़ से कम एनुअल एग्रीगेटेड टर्नओवर वाले व्यापारी और कारोबारियों की संख्या 40 हजार के करीब है।

### जीएसटी रूल्स में संसोधन

जीबीआईसी की ओर से नियमों के किए गए बदलावों को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जिसके तहत 5 करोड़ से ज्यादा एग्रीगेटेड अनुएल टर्नओवर होने पर रिटर्न के साथ जो रिकांसिलिएशन स्टेटमेंट दाखिल किया जाता है। उसे टैक्सपेयर खुद की सर्टिफाई कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट या कास्ट अकाउंटेंट के पास नहीं जाना होगा। सीनियर टैक्स एक्सपर्ट सीए दीप मिश्र बताते हैं कि जीएसटी आडिट की जरूरत को एक तरह से खत्म कर दिया है। इससे टैक्स पेयर्स को कंप्लायंस में तो राहत मिलेगी,लेकिन जानबूझकर या अंजाने में एनुअल रिटर्न में गलती होने पर परेशानी भी हो सकती है।

# आयकर विभाग ने चालू वित्त वर्ष के पहले पांच माह में 67,400 करोड़ रुपये का कर रिफंड किया

**नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क**

आयकर विभाग ने चालू वित्त वर्ष के पहले पांच माह में 67,400 करोड़ रुपये का कर रिफंड जारी किया है। आयकर विभाग ने शनिवार को ट्वीट किया, ''केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक अप्रैल, 2021 से 30 अगस्त, 2021 के दौरान 23.99 लाख करदाताओं को 67,401 करोड़ रुपये का कर रिफंड जारी किया है।'' इसमें से 22.61 लाख मामलों में 16,373 करोड़ रुपये का आयकर रिफंड किया गया है। वहीं 1.37 लाख से ज्यादा मामलों में 51,029 करोड़ रुपये के कॉरपोरेट कर का रिफंड किया गया है।

# वाणिज्य मंत्रालय ने भारत- मारीशस व्यापार समझौते के तहत आयात के लिये प्रक्रिया अधिसूचित की

**नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क**

वाणिज्य मंत्रालय ने मंगलवार को भारत- मारीशस मुक्त व्यापार समझौते के तहत मारीशस से अनानास, माल्ट बीयर, रम सहित कुछ वस्तुओं के लिये शुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) और आयात की प्रक्रिया अधिसूचित कर दी। भारत- मारीशस वृहद आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता (सीईसीपीए) एक तरह का मुक्त व्यापार समझौता है जो कि एक अप्रैल से प्रभाव में आया है। इस समझौते में भारत के लिये 310 निर्यात वस्तुओं को शामिल किया गया है। इनमें खाद्य एवं पेय पदार्थ, कृषि उत्पाद, कपड़ा और कपड़ा सामान, मूल धातु, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रनिक सामान, प्लास्टिक और रसायन तथा लकड़ी शामिल है। वहीं दूसरी तरफ मारीशस को इस समझौते के तहत भारत में उसके 615 उत्पादों के लिये तरजीही बाजार पहुंच उपलब्ध है। इनमें शीतित मछली, विशिष्ट प्रकार की चीनी, बिस्कुट, ताजा फल, जूस, खनिज जल, बीयर, एल्कोहलिक ड्रिंक, साबुन, चिकित्सा और सर्जिकल उपकरण तथा परिधान आदि शामिल हैं।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा, ''भारत- मारीशस सीईसीपीए के तहत वस्तुओं के लिये टीआरक्यू ... और इस प्रकार के आयात के लिये प्रक्रिया को अधिसूचित कर दिया गया है।'' टीआरक्यू के तहत जिन वस्तुओं के आयात की अनुमति है उसमें अनानास - 30 प्रतिशत शुल्क के साथ एक हजार टन, लींची 10 प्रतिशत शुल्क के साथ 250 टन, टयूना शून्य शुल्क पर सात हजार टन, माल्ट निर्मित बीयर 25 प्रतिशत ड्यूटी पर 20 लाख लीटर, रम शून्य ड्यूटी पर 15 लाख लीटर शामिल है। डीजीएफटी ने कहा है कि आवेदन के साथ खास सामान के मारीशस के पात्र निर्यातक के साथ खरीदारी पूर्व का समझौता भी होना चाहिये।

### तकनीकी परिधान, मानव निर्मित फाइबर के लिये

## पीएलआई योजना को मिल सकती है मंत्रिमंडल की मंजूरी

**नयी दिल्ली। एजेंसी**

केंद्रीय मंत्रिमंडल बुधवार को 10,683 करोड़ रुपये व्यय के साथ तकनीकी परिधान और मानव निर्मित रेशे (एमएमएफ) के लिये उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दे सकता है। इस पहल का मकसद घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देना है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव बुधवार को विचार के लिये मंत्रिमंडल के समक्ष आ सकता है। मंत्रिमंडल इससे पहले देश में विनिर्माण क्षमता और निर्यात को बढ़ावा देने के लिये 13 प्रमुख क्षेत्रों के लिये पीएलआई योजना को मंजूरी दे चुका है। अधिकारी के अनुसार मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद कपड़ा मंत्रालय संबंधित क्षेत्रों के लिये विस्तृत दिशनिर्देश जारी करेगा। योजना का मकसद भारत में संबंधित क्षेत्रों में समस्याओं को दूर कर, पैमाने की मितव्ययिता प्राप्त कर तथा दक्षता सुनिश्चित कर विनिर्माण को वैट्रश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाना है। इसे भारत में अनुकूल परिवेश बनाने और देश को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक अभिन्न हिस्सा बनाने के उद्श्य के साथ तैयार किया गया है। इस योजना से वैश्विक निवेश आकर्षित होने, बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होने और निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है। यह योजना घरेलू कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रमुख इकाई बनने में भी मदद करेगी। भारत के मानव निर्मित रेशे से बने कपड़ों का निर्यात उसके कुल परिधान निर्यात का केवल 10 प्रतिशत है। यह 2019-20 में लगभग 16 अरब डालर था।

# लोन लेने से लेकर बीमा कराना अब और आसान, RBI ने शुरू की सुविधा

**नई दिल्ली। एजेंसी**

***भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार से खाता एग्रीगेटर सहमति प्लेटफॉर्म सेवा को शुरू कर दिया है। इस सेवा की शुरुआत होने से ग्राहकों को लोन लेने, बीमा कराने या म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए बार-बार केवाईसी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी अब आपके लिए बैंकिंग प्रक्रिया और सरल हो गई है।***

सरल शब्दों में कहे तो खाता एग्रीगेटर आपके सभी वित्तीय ब्योरों को एक जगह से जुटा लेने का कॉमन प्लेटफॉर्म है। इस सेवा के फायदे को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं या बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए आवेदन जमा करना चाहते हैं। लोन देने या पॉलिसी जारी करने से पहले बैंक या बीमा कंपनी वित्तीय जानकारी देने को कहते हैं। इनमें बैंक खाता का डेटा, वेतन की जानकारी, दावे का रिकॉर्ड आदि शामिल होते हैं। आज अलग-अलग स्रोतों से आप यह जानकारी फिजकली जुटाते हैं। खाता एग्रीगेटर सहमति में लॉग-इन करते ही सभी जानकारी एक जगह से ली जा सकेंगी। आपकी सारी जानकारी पहले से यहां मौजूद होगी। इस तरह पूरी प्रक्रिया कम समय में और आसानी से पूरी हो जाएगी। इसमें डेटा चोरी की संभवना बहुत कम होगी कि खाता एग्रीगेटर से आपकी सहमति के बिना कोई डेटा नहीं ले पाएगा।

### ग्राहकों की रजामंदी जरूरी होगी

देश के आठ प्रमुख बैंक भारतीय स्टेट बैंक, आइसीआइसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, आइडीएफसी फर्स्ट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक व फेडरल बैंक ने खाता एग्रीगेटर नेटवर्क के साथ ग्राहकों के डेटा को साझा करने की योजना बनाई है। इससे बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को नए ग्राहक पाने में भी मदद मिलेगी। हालांकि ग्राहकों का डेटा साझा करने के लिए बैंक या वित्तीय संस्थान को उनकी रजामंदी लेनी होगी।

### सुरक्षित होगा डेटा साझा करना

डिजिटल होती दुनिया में सबसे बड़ी चिंता डेटा की सुरक्षा की है। डेटा एग्रीगेटर में आपको डेटा सुरक्षा पूरी तरह से मिलेगी। आरबीआई ने इसके लिए कड़े डेटा प्राइवेसी गाइडलाइन तैयार किए हैं। वहीं, खाता एग्रीगेटर के साथ बैंक जो डेटा शेयर करेंगे वो पूरी तरह से इंक्रिप्टेड होगा, यानी इसमें कोई सेंधमारी नहीं हो सकेगी।

## केंद्र सरकार ने एक साल की तेल बॉन्ड देनदारी का तीन गुना 4 महीने में ही कमा लिया

**नई दिल्ली। एजेंसी**

केंद्री सरकार का पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क कलेक्शन चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों में 48 प्रतिशत बढ़ गया है, और इस दौरान हासिल हुआ अतिरिक्त कलेक्शन पूरे वित्त वर्ष के दौरान तेल बॉन्ड देनदारी का तीन गुना है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत लेखा महानियंत्रक के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल-जुलाई 2021 के दौरान उत्पाद शुल्क कलेक्शन एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 67,895 करोड़ रुपये था। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद उत्पाद शुल्क केवल पेट्रोल, डीजल, एटीएफ और प्राकृतिक गैस पर लगाया जाता है। इन उत्पादों को छोड़कर अन्य सभी वस्तुएं और सेवाएं जीएसटी के तहत हैं।

### चार महीनों में 32,492 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी

वित्त वर्ष 2021-22 के पहले चार महीनों अप्रैल-जुलाई में 32,492 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई, जो पूरे साल की तेल बॉन्ड देनदारी यानी 10,000 करोड़ रुपये का तीन गुना है। कांग्रेस की अगुवाई वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन संप्रग सरकार ने पेट्रोलियम ईंधन पर सब्सिडी देने के लिए तेल बॉन्ड जारी किए थे। उद्योग सूत्रों ने कहा कि उत्पाद शुल्क कलेक्शन का बड़ा हिस्सा पेट्रोल और डीजल पर उपकर से आता है और बिक्री में तेजी के साथ ही चालू वर्ष में कलेक्शन एक लाख करोड़ रुपये से अधिक बढ़ सकता है।

## गेहूं और सरसों की MSP में बड़ा इजाफा क्या दूर होगी किसानों की नाराजगी

**नयी दिल्ली। एजेंसी**

केंद्र सरकार ने बुधवार को मौजूदा फसल वर्ष के लिए गेहूं और सरसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में इजाफे का ऐलान किया। गेहूं की एमएसपी 40 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दी गई है। इजाफे के बाद 2,015 रुपए प्रति क्विंटल की न्यूनतम कीमत पर गेहूं की खरीद होगी। इसके अलावा सरसों की एमएसपी 400 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 5,050 रुपए कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में कैबिनेट कमिटी ऑन इकॉनमिक अफेयर्स (CCEA) की बैठक में यह फैसला लिया गया है।

एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) वह कीमत है जिस पर सरकार किसानों से फसल की खरीद करती है। इस समय सरकार खरीफ और रबी सीजन के 23 फसलों के लिए एमएसपी तय करती है। रबी फसलों की बुआई अक्टूबर में खरीफ फसल की कटाई के तुरंत बाद होती है। गेहूं और सरसों रबी सीजन के दो मुख्य फसल हैं। आधिकारी रूप से दी गई जानकारी में कहा गया है कि सीसीईए ने 2021-22 फसल वर्ष और 2022-23 मार्केटिंग सीजन के लिए छह रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाई है। गेहूं की एमएसपी इस साल 40 रुपए बढ़ाकर प्रति क्विंटल 2,015 रुपए कर दी गई है, जोकि पिछले सीजन में 1,975 रुपए थी। प्रति क्विंटल गेहूं की अनुमानित लागत 1008 रुपए प्रति क्विंटल है। सरकार ने 2021-22 खरीद सीजन में रिकॉर्ड 4.3 करोड़ टन गेहूं की खरीद की थी।

# नौकरी के लिहाज से कैसा रहेगा यह वित्त वर्ष

## SBI की रिपोर्ट में आई ये बातें सामने

**नई दिल्ली।** देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई (भारतीय स्टेट बैंक) के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि वित्त वर्ष 2021-22 में श्रम बाजार की गतिविधियां सुधरेंगी और कंपनियां महामारी कम होने के साथ नियुक्ति की योजनाओं को आगे बढ़ा रही हैं। अर्थशास्त्रियों ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और नई पेंशन योजना (एनपीएस) के नियमित तौर पर जारी मासिक वेतन रजिस्टर के आंकड़ों का जिक्र किया।

मुख्य अर्थशास्त्री सौम्य कांति घोष ने एक नोट में कहा, ''हमारा अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में श्रम बाजार की गतिविधियां बेहतर रहेंगी। कंपनियां आने वाले समय में नियुक्ति योजनाओं को अमल में लाएंगी।' रोजगार को लेकर यह उम्मीद ऐसे समय जतायी गयी है,

जब दूसरी महामारी के बाद बेरोजगारों की संख्या बढ़ने और अर्थव्यवस्था में श्रम भागीदारी में कमी को लेकर चिंता जतायी जा रही है। सेंटर फार मॉनिटरिंग इंडियन एकोनॉमी (सीएमआईई) के अनुसार केवल अगस्त महीने में 15 लाख भारतीयों की नौकरियां चली गयी। इसमें 13 लाख ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। देश में रोजगार आंकड़े की कमी को लेकर विभिन्न तबकों में चिंता जतायी जाती रही है। ईपीएफओ और एनपीएस के रोजगार के आंकड़े की आलोचना की जाती रही है क्योंकि यह केवल संगठित क्षेत्र में नौकरियों तक सीमित है। जबकि बहुत सारा काम असंगठित क्षेत्र में होता है। घोष ने कहा, ''क्षेत्र को संगठित रूप देने की दर 10 प्रतिशत है। कुल नियमित रोजगार (पेरोल) में नई नौकरी का अनुपात 50 प्रतिशत है। यह बताता है कि प्रत्येक दो रोजगार में एक नियमित नौकरी में नया जुड़ाव है। यह वित्त वर्ष 2020-21 में 47 प्रतिशत था। यानी इसमें सुधार हुआ है।' एसबीआई के अर्थशास्त्रियों की रिपोर्ट के अनुसार जून तिमाही में 30.74 करोड़ नियमित नौकरियां सृजित हुई। इसमें 16.3 लाख नई नौकरियां थी, जो पहली बार ईपीएफओ या एनपीए से जुड़े। इसमें कहा गया है कि अगर नई नौकरियों में इसी रफ्तार से बढ़ोतरी होती रही तो यह 2021-22 में 50 लाख पार कर सकता है जो 2020-21 में 44 लाख था। रिपोर्ट के अनुसर अच्छी बात यह है कि शुद्ध रूप से ईपीएफओ अंशधारकों की संख्या वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में बढ़ी है। यह बताता है कि महामारी की दूसरी लहर के दौरान श्रम बाजार में ज्यादा समस्याएं नहीं आयी।

## रुपया 18 पैसे टूटकर 73.60 रुपये प्रति डॉलर पर पहुंचा

मुंबई। विदेशी बाजारों में अमेरिकी मुद्रा में मजबूती तथा घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट के बीच बुधवार को रुपया 18 पैसे गिरकर 73.60 (अस्थायी) प्रति डॉलर पर आ गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में कारोबार की शुरुआत में रुपया 73.48 प्रति डॉलर पर खुलने के बाद 73.70 रुपये प्रति डॉलर के निचले स्तर तक गया। बाद में यह पिछले बंद स्तर से 18 पैसे टूटकर 73.60 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के शोध विश्लेषक दिलीप परमार ने कहा, ''रुपये में लगातार तीसरे दिन गिरावट रही। प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती से रुपया प्रभावित हुआ। कंपनियों की बड़ी निकासी, वैश्विक स्तर पर बांड प्राप्ति में बढ़ोतरी तथा डॉलर मांग की हेजिंग से रुपये की धारणा प्रभावित हुई।'' इस बीच, छह मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी मुद्रा का रुख दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.23 प्रतिशत की बढ़त के साथ 92.72 पर पहुंच गया। वहीं ब्रेंट कच्चा तेल वायदा 0.80 प्रतिशत बएक़र 72.26 डालर प्रति बैरल पर पहुंच गया।

# रिलायंस जियो के 5 सालः 'डेटा इज न्यू ऑयल' नारे ने यूं बदली तस्वीर

## देश में 1300% बढ़ी खपत

**नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क**

**पांच साल पहले जब मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो के लॉन्च की घोषणा की तो किसी को भी अंदाजा नहीं था कि जियो, देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ साबित होगी। भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुए 26 वर्ष बीत गए हैं। कई टेलिकॉम कंपनियों ने इस सेक्टर में हाथ अजमाया, पर कमोबेश सभी कंपनियों का फोकस वॉइस कॉलिंग पर ही था। 5 सितंबर 2016 को जियो की लॉन्चिंग पर मुकेश अंबानी ने 'डेटा इज न्यू ऑयल' का नारा दिया और इस सेक्टर की तस्वीर ही बदल गई।**

### 5 साल पहले कितनी थी डेटा की खपत

अक्टूबर से दिसंबर 2016 की ट्राई की परफॉरमेंस इंडीकेटर रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि उस वक्त प्रति यूजर डेटा की खपत मात्र 878.63 एमबी थी। सितंबर 2016 में जियो के लॉन्च के बाद डेटा खपत में जबर्दस्त उछाल आया और यह 1303 फीसदी बढ़कर 12.33 जीबी हो गई। जियो के लॉन्च होने के बाद टेलिकॉम सेक्टर में प्राइस वॉर और डेटा वॉर छिड़ी। जियो के सस्ते डेटा की पेशकश की देखादेखी बाकी टेलिकॉम कंपनियों ने भी अपने ग्राहकों को जोड़े रखने के लिए प्लान्स की कीमतें घटाईं। ग्राहकों को कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा डेटा उपलब्ध कराने की होड़ सी मच गई।

### आज 4 गुना ज्यादा ब्रॉडबैंड ग्राहक

जियो के मार्केट में उतरने के बाद केवल डेटा की खपत ही नही बढ़ी डेटा यूजर्स की संख्या में भी भारी इजाफा देखने को मिला। ट्राई की ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल पहले के मुकाबले ब्रॉडबैंड ग्राहकों की तादाद 4 गुना बढ़ चुकी है। जहां सितंबर 2016 में 19.23 करोड़ ब्रॉडबैंड ग्राहक थे, वहीं जून 2021 में यह संख्या 79.27 करोड़ हो गई। विशेषज्ञों का मानना है कि डेटा की खपत में बढ़ोतरी और इंटरनेट यूजर्स की तादाद में भारी इजाफे की वजह डेटा की कीमतों में आई कमी है।

दरअसल जियो की लॉन्चिंग से पूर्व तक 1 जीबी डेटा की कीमत करीब 160 रुपये प्रति जीबी थी, जो 2021 में घटकर 10 रुपये प्रति जीबी से भी नीचे आ गई। यानी पिछले 5 वर्षों में देश में डेटा की कीमतें 93% कम हुईं। डेटा की कम हुई कीमतों के कारण ही आज भारत, दुनिया में सबसे किफायती इंटरनेट उपलब्ध कराने वाले देशों की लिस्ट में शामिल है।

### सस्ते डेटा ने कराए क्या फायदे

डेटा की कीमतें कम हुईं तो डेटा खपत बढ़ी। डेटा खपत बढ़ी तो डेटा की पीठ पर सवार काम धंधों के पंख निकल आए। आज देश में 53 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं, जो जियो की डेटा क्रांति से पहले तक 10 हुआ करती थीं। ई-कॉमर्स, ऑनलाइन बुकिंग, ऑर्डर प्लेसमेंट, ऑनलाइन एंटरटेनमेंट, ऑनलाइन क्लासेज जैसे शब्दों से भारत का अमीर तबका ही परिचित था। आज रेलवे बुकिंग खिड़कियों पर लाइनें नहीं लगतीं। खाना ऑर्डर करने के लिए फोन पर इंतजार नही करना पड़ता। किस सिनेमा हॉल में कितनी सीटें किस रो में खाली हैं, बस एक क्लिक में पता चल जाता है। यहां तक कि घर की रसोई की खरीदारी भी ऑनलाइन माल देख परख कर और डिस्काउंट पर की जा रही है। भुगतान के लिए, आज बड़ी संख्या में ग्राहक नकदी छोड़ कर डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने लगे हैं। इस डिजिटल शिफ्ट में रिलायंस जियो की बड़ी भूमिका है। 2016 के बाद से ही देश में डिजिटल लेन देन का मूल्य और आकार दोनों बढ़े हैं।

### रोजगार के अवसर भी बने

ऑनलाइन धंधे चल निकले तो उनकी डिलीवरी के लिए भी एक पूरा जाल खड़ा करना पड़ा। मोटरसाइकिल पर किसी खास कंपनी का समान डिलीवर करने वाले कर्मचारी का सड़क पर दिखाई देना अब बेहद आम बात है। मोटर साइकिल के पहिए घूमे तो हजारों लाखों परिवारों को रोजी रोटी मिली। जोमैटो के सीइओ ने कंपनी के आईपीओ लिस्टिंग के महत्वपूर्ण दिन रिलायंस जियो को धन्यवाद दिया। यह धन्यवाद यह बताने के लिए काफी है कि रिलायंस जियो, भारतीय इंटरनेट कंपनियों के लिए क्या मायने रखती है। नेटफ्लिक्स के सीईओ रीड हैस्टिंग्स ने उम्मीद जताई थी कि काश जियो जैसी कंपनी हर देश में होती और डेटा सस्ता हो जाता।

# कैबिनेट ने टेक्सटाइल सेक्टर को दी 10683 करोड़ रुपये की मंजूरी, सरकार का ये है प्लान

**नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क**

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम के तहत 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की मंजूरी दी है। इस सेक्टर को 5 वर्षों में 10,683 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया, आगामी 5 वर्षों में 10,683 करोड़ रुपये मूल्य के प्रोत्साहन मुहैया कराए जाएंगे। प्रत्यक्ष तौर पर 7.5 लाख से ज़्यादा लोगों के लिए रोज़गार के अवसर पैदा होंगे।

वहीं, केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इसका लाभ लेते हुए भारत अब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अपना वर्चस्व और दिखा पाएगा। विकसित देशों के साथ भी एफटीए करके हम कपड़ा व्यापार में बाकी देशों के सामने जो हमारी डिसेबिलिटी है उसे कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल देश में मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और निर्यात को बढ़ावा देने के लिये 13 प्रमुख क्षेत्रों के लिये पीएलआई योजना को मंजूरी दे चुका है।

योजना का क्या है मकसदः योजना का मकसद भारत में संबंधित क्षेत्रों में समस्याओं को दूर कर मैन्युफैक्चरिंग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाना है। इसे भारत में अनुकूल परिवेश बनाने और देश को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक अभिन्न हिस्सा बनाने के मकसद के साथ तैयार किया गया है। इस योजना से वैश्विक निवेश आकर्षित होने, बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होने और निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है। यह योजना घरेलू कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रमुख इकाई बनने में भी मदद करेगी। बता दें कि भारत के मानव निर्मित रेशे से बने कपड़ों का निर्यात उसके कुल परिधान निर्यात का केवल 10 प्रतिशत है। यह 2019-20 में लगभग 16 अरब डॉलर था।

# ओएनजी विदेश की रूस के वोस्तोक, आर्कटिक एलएनजी-2 परियोजना में हिस्सेदारी खरीदने को लेकर बातचीत

**नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क**

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ओएनजीसी विदेश लि. समेत भारत की प्रमुख ऊर्जा कंपनियां रूस की प्रमुख वोस्तोक तेल परियोजना में हिस्सेदरी खरीदने पर बातचीत कर रही हैं। साथ ही वे तरलीकृत गैस परियोजना आर्कटिक एलएनजी-2 को लेकर भी विचार कर रही हैं।

ओएनजीसी विदेश लि. (ओवीएल)सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) की विदेश में कारोबार करने वाली इकाई है।

ओवीएल वोस्तोक तेल परियोजना में अल्पांश हिस्सेदारी खरीदने पर गौर कर रही है। इस परियोजना के अंतर्गत 6 अरब टन यानी करीब 44 अरब बैरल प्रीमियम कच्चा तेल होने का अनुमान है। ओवीएल, पेट्रोनेट एलएनजी लि. के साथ नोवातेक से 9.9 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने को लेकर भी बातचीत कर रही है। पूर्वी आर्थिक मंच की बैठक में भाग लेने रूस गये पुरी ने भारत रवाना होने से पहले मास्को में संवाददाताओं से कहा, ''कई नये संभावित निवेश ...वोस्तोक ऑयल, आर्कटिक एलएनजी-2 .. और -.. पेट्रोकेमिकल्स पर चर्चा की गयी। पूर्वी आर्थिक मंच की बैठक व्लादिवोस्तोक में थी।

मीडिया से बातचीत का संक्षिप्त अंश ट्विटर पर डालते हुए उन्होंने लिखा है कि ये निवेश रूस और भारत के बीच संबंध को और प्रगाढ़ बनाएंगे। पुरी ने ट्विटर पर लिखा है, ''मास्को में मीडिया के सदस्यों के साथ बातचीत में, मैंने उन्हें ऊर्जा सुरक्षा क्षेत्र के महत्वपूर्ण भागीदार रूस की सार्थक यात्रा के बारे में जानकारी दी।''

उन्होंने कहा कि उनकी अगुवाई में गये प्रतिनिधिमंडल की रूस की आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के साथ कई बैठकें हुई।

रूस के ऊर्जा मंत्री निकोले शुलगिनोव ने कहा कि रोसनेफ्ट, गाजप्रोम नेफ्ट और नोवातेक सहित लगभग सभी प्रमुख कंपनियों की भारतीय तेल और गैस कंपनियों के साथ नई परियोजनाओं को विकसित करने में रुचि है। शुलगिनोव ने रूसी-भारतीय व्यवसायिक वार्ता में कहा, ''हम सभी क्षेत्रों में ऊर्जा सहयोग की संभावनाएं देखते हैं।'' पुरी के अनुसार भारतीय तेल कंपनियां पहले ही रूस के तेल और गैस क्षेत्र में लगभग 16 अरब डालर का निवेश कर चुकी हैं। इसमें सखालिन -1, वेंकोर और तास-यूरीअख जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। रूस ने भारत में इतनी ही राशि का निवेश किया है। मंत्री ने अपनी 5 दिवसीय यात्रा के दौरान रोसनेफ्ट के सीईओ इगोर सेचिन से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सेचिन ने वोस्तोक तेल वृहत परियोजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने यात्रा के दौरान नोवातेक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी लियोनीद मिखेलसन से भी मुलाकात की।

# अरुण कुमार सिंह ने बीपीसीएल के नए चेयरमैन का पद संभाला, गुप्ता नए निदेशक-वित्त

***नयी दिल्ली। एजेंसी***

***अरुण कुमार सिंह ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि.( बीपीसीएल ) के नये चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक का पदभार संभाल लिया है। कंपनी ने बुधवार को यह जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि सरकार बीपीसीएल के निजीकरण की तैयारी कर रही है। इसके अलावा वी रामकृष्ण गुप्ता देश की दूसरी सबसे बड़ी पेट्रोलियम विपणन कंपनी के नए निदेशक ( वित्त ) होंगे। सरकार की ओर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शीर्ष अधिकारियों का चयन करने वाले लोक उपक्रम चयन बोर्ड ( पीईएसबी ) ने इस साल मई में सिंह को इस पद के लिए चुना था। यह पद अगस्त, 2020 में डी राजकुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद रिक्त हुआ था।***

शुरुआत में यह माना जा रहा था कि सरकार चाहती है कि बीपीसीएल के नए चेयरमैन का नाम कंपनी के निजीकरण के बाद नए प्रबंधन के आने के पश्चात किया जाए। पीईएसबी ने 10 मई को संभावित उम्मीदवारों का इस पद के लिए साक्षात्कार लेने के बाद सिंह का चयन किया। इससे पहले वह बीपीसीएल के निदेशक (विपणन) थे। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने इससे पहले इसी सप्ताह उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी। उसके बाद सिंह ने बीपीसीएल के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक का पदभार संभाल लिया है।

सरकार बीपीसीएल में अपनी समूची 52.98 प्रतिशत हिस्सेदारी रणनीतिक खरीदार को बेच रही है। अनिल अग्रवाल के वेदांता समूह सहित तीन समूहों ने बीपीसीएल की हिस्सेदारी के अधिग्रहण में रुचि दिखाई। बीपीसीएल ने बयान में कहा कि सिंह के पास तेल एवं गैस उद्योग का 36 साल से अधिक का अनुभव है। वह बीपीसीएल और गेल (इंडिया) लि. के शहर गैस संयुक्त उद्यम इंद्रप्रस्थ गैस लि. के चेयरमैन भी रह चुके हैं। इसके अलावा वह बीपीसीएल की अनुषंगी भारत गैस रिसोर्सेज के निदेशक मंडल में भी रहे हैं। वहीं रामकृष्ण निदेशक वित्त के पद पर पदोन्नति से पहले कंपनी के मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) थे। गुप्ता ने एन विजयगोपाल का स्थान लिया है, जो 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हुए हैं।

# अखंड सौभाग्य का प्रतीक है हरतालिका व्रत

## भगवान शिव-माता पार्वती से जुड़ी व्रत कथा

**भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हरितालिका तीज के नाम से शिव-पार्वती भक्तों में लोकप्रिय है। यह पर्व शिव-पार्वती के अखंड जुड़ाव का प्रतीक है। समाज में पति और पत्नी के बीच जो जुड़ाव है, वह क्या है? क्या इनके मध्य कोई ऐसी डोर भी है, जो हमको एक शांत और मंगलकारी परिवार की ओर ले जाती है? दूसरा प्रश्न... परिवार तो अन्य देवों के भी हैं, लेकिन सनातन संस्कृति में शिव परिवार ही क्यों आदर्श बना?**

भगवान शंकर और पार्वती के मिलन के कई प्रसंग हमारे लिए आदर्श हैं। शिव पुराण से लेकर श्रीरामचरितमानस तक अनेक ग्रंथों में शिव और पार्वती को श्रद्धा और विश्वास की संज्ञा दी गई है। श्रद्धा पार्वती जी हैं और विश्वास साक्षात भगवान शंकर हैं। जब एक-दूसरे के प्रति श्रद्धा और विश्वास होगा, तो वह आदर्श परिवार होगा। जहां इनमें से किसी एक की भी कमी होगी, परिवार संकट और क्लेश में घिर जाएगा। शिव प्रसंग में दो स्त्री आती हैं। एक सती और दूसरी पार्वती।

हम पार्वती के रूप में स्त्री को अंगीकार करते हैं। क्यों? पार्वती जी को ही हमने अक्षत सुहाग की अधिष्ठात्री माना है, क्योंकि वहां समर्पण है। सती प्रसंग में अपनी जिद है, लेकिन पार्वती के रूप में हर स्त्री सौभाग्यवती है। हरतालिका तीज का प्रसंग भी इसी से जुड़ा है। अविवाहिताओं के लिए मुख्य रूप से यह व्रत है, जो पूर्वांचल और बिहार आदि में प्रमुखता से किया जाता है। पश्चिमांचल में यही व्रत सावन में तीजोत्सव के रूप में आता है। हरतालिका तीज भादों (भाद्रपद) मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को होती है। दोनों की कथा एक ही है, लेकिन मर्म व्यापक है।

पूर्वजन्म में सती होने के बाद देवी ने अगले जन्म में पार्वती के रूप में अवतरण किया। भगवान शंकर को पाने के लिए घोर तप किया। अन्न-जल त्याग दिया। उनका शरीर पर्ण के समान हो गया। यहीं से देवी का नाम अपर्णा पड़ा। भूख और प्यास को सहन करते हुए देवी ने केवल एक ही प्रण किया कि वह शंकर जी को ही वरण करेंगी। तप तो पूरा हुआ, लेकिन भगवान शंकर कहां मानने वाले थे। कथा आती है कि तारकासुर के संहार के लिए शंकर जी ने पार्वती से विवाह किया, क्योंकि तारकासुर को वरदान प्राप्त था कि शंकर जी के पुत्र (गर्भ से उत्पन्न) द्वारा ही वह मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। अंततोगत्वा कार्तिकेय के रूप में पार्वती जी ने पुत्र को जन्म दिया और तब जाकर तारकासुर से मुक्ति मिली।

हरतालिका तीज इच्छित वर की कामना का व्रत है। इच्छित वर की कामना को गलत नहीं माना नहीं गया। वरन इसके व्रत भी हैं। हरितालिका इसमें से एक है। कालांतर में, सुहागिन स्त्रियां भी व्रत को करने लगीं। पार्वती जी की तरह निर्जल रहने लगीं। मुख्य उद्देश्य एक ही है शिव ही शिव हो, यानी कल्याण। परिवार में भी और दाम्पत्य जीवन में भी।

शिव कल्याण के देव हैं और पार्वती जी कल्याणी। पारिवारिक और वैवाहिक, सभी संस्कारों की नींव शिव परिवार से ही पड़ी। यह सुखी और आदर्श परिवार है। इसमें कार्तिकेय के रूप में गर्भोत्पन्न शिशु भी हैं, तो मानस पुत्र के रूप में गणेश जी भी। अशुभता और शुभता का संकेत देने वाला नादिया भी है तो श्रद्धा के रूप में साक्षात पार्वती जी भी हैं। इन सभी का विश्वास शिव में है। शिव का विश्वास इनमें है। इसलिए, शिव परिवार सुखी परिवार है। जिस तरह माता पार्वती का सुहाग अक्षत है, उसी तरह व्रत को करने वालों का भी हो, यही कामना सनातन है। यही हरतालिका है। हम सभी परिवार के लिए कुछ न कुछ समर्पण करते हैं। अन्न-जल का त्याग इसी संकल्प का हिस्सा है। सब सुखी हों, सभी का परिवार श्रद्धा व विश्वास के साथ फूले-फले, यही कामना हमको और हमारी संस्कृति को पल्लवित करती है।

# आ रहे हैं श्री गणेश

## 10 दिनों तक अर्पित करें 10 सामग्रियां, खुश होंगे गणपति

भाद्रपद की चतुर्थी को 10 दिवसीय गणेश उत्सव का प्रारंभ होता जो अनंत चतुर्दशी तक चलता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस बार 10 सितंबर 2021 से गणपति उत्सव प्रारंभ होगा जो 19 सितंबर तक चलेगा। 10 दिनी उत्सव में गणपतिजी को 10 दिन तक भिन्न-भिन्न प्रकार का भोग लगाया या प्रसाद अर्पित किया जाता है। आओ जानते हैं कि कौनसी प्रमुख 10 सामग्री उन्हें अर्पित की जा सकती है।

1. **लड्डू :** गणेशजी को मोदक के लड्डू बड़े प्रिय हैं। मोदक भी कई तरह के बनते हैं। जैसे उखड़ी के मोदक, नारियल और तील के मोदक आदि। इसके अलावा उन्हें मोतीचूर अर्थात बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, सूजी के लड्डू, गुड़ के लड्डू और राजगिरे के लड्डू भी अर्पित किए जाते हैं।
2. **नारियल चावल :** यह दक्षिण भारत में बनाया जाता है। नारियल के दूध या पानी में चावल को भिगोगर या नारियल के गुदे को चावल में मिलाकर पकाने से बनना है।
3. **सतोरी या पुरण पोली :** यह खोआ या मावा, घी, बेसन और दूध से बना एक महाराष्ट्रीय व्यंजन है। यह रोटी की तरह गोल होता है। पुराण पोली में चले की दाल में गुढ़ मिलाकर उसे मिसकर उसे रोटी में भरा जाता है। जैसे आलू का पराठा बनता है उसी तरह से यह पुरण पोली बनाई जाती है।
4. **श्रीखंड :** केसर मिला पीला श्रीखंड का भोग भी उन्हें लगाया जाता है। दही से बने इस मिष्ठान में किशमिश और चारोली मिलाकर इसके भोग लगाएं। श्रीखंड के अलावा आप पंचामृत या पंजरी का भी भोग लगा सकते हैं।
5. **केले का शीरा :** मैश किए हुए केले, सूजी और चीनी से बना शीरा सूची के हलवे की तरह होता है। यह भी गणेशजी का प्रिय भोजन माना जाता है। उन्हें केले का प्रसाद भी अति प्रिय है। केले का ये प्रसाद हाथी को भी खिलाना चाहिए।
6. **रवा पोंगल :** इसे रवा अर्थात सूजी और मूंग के सात घी डालकर बनाया जाता है। इसमें किशमिशल काजू और बादाम डाला जाता है। इसे मूंग का हलवा ही मानें। इसके अलावा आपन चाहें तो सूजी के हलवे का भोग भी लगा सकते हैं।
7. **पयसम :** यह भी एक पारंपारिक दक्षिण भारतीय खीर है। इसे दूध और चीनी या गुड़ के साथ बनाया जाता है और फिर इसमें चावल या सेंवई मिलाई जाती है। अंतिम रूप से इलायची पाउडर, घी और अन्य ड्राई फ्रूट्स को इसमें परम स्वाद और गार्निशिंग के लिए डाला जाता है। आप चाहें तो राईस या साबूदाने की खीर भी बना सकते हैं।
8. **शुद्ध घी और गुड़ का भोग लगाएं :** उन्हें शुद्ध घी में देशी गुड़ मिलाकर उसका भी भोग लगते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो भगवान गणेश को चतुर्थी के दिन आप छुआरे, परमल, नारियल और मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं।
9. **दुर्वा :** गणेश जी को भोग के साथ दुर्वा भी चढ़ाई जाती है। उन्हें 21 गुड़ की ढेली के साथ दूर्वा चढ़ाने से सभी तरह की मनोकामना पूर्ण होती है।
10. **शभी के पत्ते :** गणेश जी को भोग के साथ शमी के पत्ते भी अर्पित किए जाते हैं। शमी भी गणेशजी को अत्यंत प्रिय है। शमी के कुछ पत्ते नियमित गणेश जी को अर्पित करें तो घर में धन एवं सुख की वृद्धि होती है। अगर आपके जीवन में बहुत परेशानियां हैं, तो आप गणेश चतुर्थी के दिन हाथी को हरा चारा खिलाएं।

# गणेश चतुर्थी पर इस शुभ मुहूर्त में करें गणपति स्थापना

प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन 10 दिवसीय गणेशोत्सव पर्व मनाया जाता है। यह दिन श्री गणेश चतुर्थी के नाम से प्रचलित है। इस दिन श्री गणेश जी की प्रतिमा घर लाने और 10 दिनों तक उनका विधि-विधान से पूजन करने की परंपरा है। इस वर्ष 10 सितंबर 2021, शुक्रवार को यह पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन चित्रा नक्षत्र रहेगा और ब्रह्म योग रहेगा। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ गुरुवार, 9 सितंबर 2021 को रात 12:17 से होकर शुक्रवार, 10 सितंबर 2021 रात्रि 10:00 बजे तक चतुर्थी तिथि रहेगी। इस दिन पाताल लोक की भद्रा रहेगी, जिसका समय सुबह 11:08 मिनट से रात 9:57 मिनट तक होगा। वैसे तो भद्रा काल को शुभ कार्य के लिए अशुभ माना जाता है, किंतु श्री गणेश का एक अन्य नाम विघ्नविनाशक भी है, अतः भद्रा की वजह से गणेश स्थापना प्रभावित नहीं होगी। इस बार श्री गणेश जी की

स्थापना चित्रा नक्षत्र के ब्रह्म योग में होगी और चित्रा नक्षत्र दोपहर 12:58 मिनट तक रहेगा। उसके बाद स्वाती नक्षत्र प्रारंभ होगा। इस दिन रवि योग भी रहेगा, जिसका समय सुबह 6:01 मिनट से लेकर दोपहर 12:58 मिनट तक रहेगा। यह संयोग सुख-समृद्धि और सौभाग्य देने वाला साबित होगा।

आइए जानें किस शुभ मुहूर्त में करें गणेश स्थापना कि जीवन मंगलमयी हो जाएं-

### गणेश चतुर्थी स्थापना के सबसे शुभ मुहूर्त

रवि योग- सुबह 6:01 से दोपहर 12:58 मिनट तक रहेगा।

अमृत काल- प्रातः 06:58 से सुबह 08:28 मिनट तक रहेगा।

अभिजीत मुहूर्त- प्रातः 11:30 से दोपहर 12:20 मिनट तक रहेगा।

विजय मुहूर्त- दोपहर 01:59 से 02:49 मिनट तक रहेगा।

गोधूलि मुहूर्त- शाम 05:55 से 06:19 मिनट तक रहेगा।

मध्याह्न गणेश पूजा मुहूर्त- प्रातः 11:03 से दोपहर 01:32 बजे तक रहेगा।

# गणेशजी के सबसे खास 3 अनसुलझे रहस्य

भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेशजी का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक गणेश उत्सव मनाया जाता है। इस बार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 10 सितंबर से 19 सितंबर 2021 तक यह महोत्सव चलेगा। आओ जानते हैं गणेशजी के 3 सबसे खास अनसुलझे रहस्य।

**1. गणेशजी का जन्म कैसे हुआ :** गणेशजी के जन्म के 3 रहस्य है। पहला गणेशजी को माता पार्वती ने अपने शरीर के मेल या दुर्वा से बनाया था, दूसरा माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तप किया और पुण्यक नामक उपवास या व्रत किया था जिसके चलते गणेशजी का जन्म हुआ था, तीसरा वराहपुराण के मुताबिक भगवान शिव ने गणेशजी को पचंतत्वों से बनाया है।

**2. गणेशजी का सिर कैसे कटा :** कहते हैं कि शनि भगवान की दृष्टि पड़ने से उनका सिर धड़ से अलग होकर चंद्रलोक में चला गया था। बाद में एक हथनी के पुत्र का सिर काटकर उनके धड़ पर लगाया गया। यह भी कहते हैं कि उनका सिर शिवजी ने काट दिया था और बाद में एक हथनी के पुत्र का सिर काटकर उनके धड़ पर लगाया गया।

**3. गणेश जी का दांत कैसे टूटा :** कहते हैं कि एक बार गणेशजी के बड़े भाई कार्तिकेय एक ग्रंथ लिख रहे थे। उनके इस कार्य में गणेशजी ने विघ्न डाल दिया जिससे क्रोधित होकर कार्तिकेय ने उनके एक दांत को पकड़कर तोड़ दिया। यह कथा संभवतः भविष्य पुराण के चतुर्थी कल्प में है। दूसरी कथा हमें गशेण पुराण के चतुर्थ खंड में मिलती है कि एक बार शिवजी की तरह ही गणेशजी ने कैलाश पर्वत पर जाने से परशुरामजी को रोक दिया था। तब क्रोधित होकर परशुरामजी ने शिवजी के दिए हुए फरसे का उन पर प्रयोग किया जिसके चलते गणेशजी का बायां दांत टूट गया। तीसरी कथा के अनुसार गजमुखासुर नामक असुर को वरदान प्राप्त था कि वह किसी भी अस्त्र-शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। इसीलिए गणेशजी को अपने एक दांत तोड़कर उसका वध करना पड़ा। चौथी कथा के अनुसार महर्षि वेद व्यासजी ने गणेशजी से महाभारत लिखने की प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि इस शर्त पर लिखूंगा कि आप बीच में ही बोलना ना रोगेंगे। तब महर्षि ने भी एक शर्त की आप जो भी लिखेंगे वह उसे समझकर ही लिखेंगे। गणेशजी भी शर्त मान गए। अब दोनों ने काम शुरू किया और महाभारत के लेखन का काम प्रारंभ हुआ। महर्षि के तेजी से बोलने के कारण कुछ देर लिखने के बाद अचानक से गणेशजी की कलम टूट गई। अब अपने काम में बाधा को दूर करने के लिए उन्होंने अपने एक दांत को तोड़ दिया और स्याही में डूबाकर महाभारत की कथा लिखने लगे।

# हिमाचल के साथ अब आने लगा कश्मीर से भी सेब, आवक बढ़ी तो सस्ता हो गया

यह बात तो आप जानते ही होंगे कि सेब पैदा तो हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में होता है, लेकिन इसका ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन दिल्ली से होता है। दिल्ली में अब हिमाचल प्रदेश के साथ साथ कश्मीरी सेबों की भी आवक शुरू हो गई है। इससे जहां लोगों के पास सेबों की वेराइटी बढ़ी है वहीं इसकी कीमत भी घट गई है। सेब का डिस्ट्रीब्यूशन हब दिल्ली है। दिल्ली से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र समेत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु भी सेब जाता है। इसलिए सेब के व्यापारियों के लिए दिल्ली महत्वपूर्ण बाजार है।

### इन कारणों से नहीं है सेब की कीमतों में उछाल

कश्मीर एप्पल मर्चेंट एसोसिएशन के वाइस प्रेजिडेंट विजय तालरा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश से रोजाना 80 से 100 ट्रक और कश्मीर से 50 से 70 ट्रक सेब दिल्ली पहुंच रहा है। एक ट्रक में सेब की करीब 600 से 650 पेटियां होती हैं। प्रत्येक पेटी में 15 से 16 किलो सेब होता है। हालांकि, इस समय देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ है। इस वजह से सेब की डिमांड भी घटी है। लिहाजा सेब की कीमतों में उछाल नहीं है।

कश्मीरी सेब की आ रही हैं ज्यादा वैरायटी

विजय तालरा ने बताया कि कश्मीर के सेब की ज्यादा वैरायटी (Variety of Kashmiri Apples) आ रही हैं। थोक में कश्मीरी सेब 50 रुपये से 130 रुपये किलो में उपलब्ध है। मंडी में सेब की दूसरी वैरायटी 30 रुपये से 60 रुपये किलो बिक रही है। कश्मीरी बब्बू गोशा (Babbo gosha of Kashmir) भी 30 से 80 रुपये किलो की दर से मिल रहा है। बाजार में दोनों फलों की कमी नहीं है।

### सेब कारोबार पर नहीं कोविड-19 का असर

विजय तालरा का कहना है कि राहत की बात है कि अब कोविड-19 का असर सेब कारोबार पर नहीं है। देश के कई हिस्सों में कोरोना के केस घटे हैं। आजादपुर मंडी में 500 से ज्यादा आदमी सेब बेचते हैं। अगले 10 से 15 दिनों में कश्मीरी सेबों की वैरायटी बढ़ जाएगी। सेब के आकार के हिसाब से दाम निर्धारित होते हैं। हिमाचल का सेब अभी बेहतर आ रहा है और उसके दाम अधिक हैं, जबकि कश्मीर के सेब की शुरुआत है।

### रॉयल क्वालिटी का सेब सबसे पसंदीदा

शिमला एप्पल मर्चेंट एसोसिएशन के खजांची जिम्मी खेलानी का कहना है कि इस समय मार्केट में हिमाचली सेबों की आवक अच्छी है। अब तो पहले के मुकाबले सेब की क्वालिटी भी बेहतर हुई है। दिल्ली में 200 से ज्यादा आढ़ती शिमला और कुल्लू के सेबों का बिजनेस करते हैं। सेबों में सबसे ज्यादा रॉयल क्वालिटी को पसंद किया जाता है। इसी का सीजन चल रहा है। अभी गोल्डन और रेड गोल्ड सेब की किस्म कम आ रही हैं। हिमाचल में अच्छी फसल होने का लाभ आम लोगों को भी मिल रहा है। सेब के रेट्स ज्यादा नहीं बढ़े हैं, लिहाजा आम आदमी की पहुंच में हैं। रिटेल मार्केट में 60 से 100 रुपये में सेब मिल रहा है।

### दिल्ली है सेब का डिस्ट्रीब्यूशन हब

सेब पैदा भले ही दूसरे राज्यों में होता है, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन हब दिल्ली है। दिल्ली से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) समेत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु भी सेब जाता है। इस समय शिमला से रोजाना 1500 से 2500 टन सेब दिल्ली आ रहे हैं। इनमें से 40 फीसदी सेब की खपत दिल्ली-एनसीआर के शहरों में रह जाते हैं। शेष 60 फीसदी सेब देश के दूसरे हिस्सों में जाने के लिए ट्रकों में लोड हो जाते हैं। अब हिमाचल प्रदेश में भी जगह-जगह सेब की मंडियां बन गई हैं। वहां से भी तमाम राज्यों में डायरेक्ट सेब लोड हो रहा है। इससे ट्रेडर्स का समय और पैसा दोनों बच रहा है।

# ईवी स्कूटर बाजार में एक और मजबूत दावेदारी, एलएमएल भी कूदने को तैयार

**नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क**

कानपुर की लोहिया मशीन्स या एमएमएल (LML) को तो जानते ही होंगे। एक जमाने में एलएमएल वेस्पा स्कूटर के जरिए इसने देश भर में खासी लोकप्रियता हासिल की थी। अब यह कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में उतरने की तैयारी में है। खबर है कि इसने किसी अन्य कंपनी को पार्टनर बनाया है और वहां से एलएमएल को बड़ा निवेश मिला है।

### कई टेक्नोलॉजी कंपनियों से मिला है प्रस्ताव

सूत्रों के मुताबिक, प्रबंधन ने ईवी बाजार में एलएमएल को बाजार में उतारने के लिए विभिन्न टेक्नोलॉजी कंपनियों से प्रस्ताव हासिल कर लिया है। कंपनी का दावा है कि एक शानदार उत्पाद पेश करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब इंतजार है प्रोडक्ट के बनने का ताकि कंपनी को खोई हुई पुरानी पहचान फिर से मिल सके।

### बहुत गंभीरता से हो रहा है काम

एलएमएल इलेक्ट्रिक के एमडी और सीईओ डॉ. योगेश भाटिया ने इस बारे में बताया, 'हम जबर्दस्त वापसी को लेकर बहुत ही उत्साहित हैं। हम बेहतरीन तकनीकी की मदद से अत्यंत अभिनव उत्पाद पेश करने के लिए उत्पाद विकास रणनीतियों पर बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं ताकि शहरी आबादी में लोगों की आवाजाही सुगम और सफल हो सके। हम अपने प्रीमियम रेंज के उत्पादों के जरिये उच्च मध्यवर्ग और शहरी आबादी को सक्षम बनाना चाहते हैं जिससे उनके दोपहिया चलाने का अनुभव और तौर-तरीका ही बदल जाएगा।'

### 1972 में हुई है स्थापना

वर्ष 1972 में स्थापित एलएमएल भारत की लोकप्रिय दोपहिया निर्माता कंपनी रही है। कंपनी उत्तर प्रदेश के कानपुर में अवस्थित है। यह स्कूटर मोटरसाइकिल और मोपेड के अलावा इनके स्पेयर पार्ट और कल-पुर्जे बनाती है। इससे पहले 1983 में कंपनी ने पियाजियो वेस्पा इटली के तकनीकी सहयोग से 100 सीसी के स्कूटर बनाना शुरू किया था और इसके साथ कई लाइसेंसिंग समझौते किए थे।लगातार वृद्धि दर्ज की और कई वाहन परियोजनाएं भी शुरू कीं।

# मप्र सरकार ने बांस आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए 2.77 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की

**भोपाल। आईपीटी नेटवर्क**

मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बांस आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए 2.77 करोड़ रुपये का अनुदान निर्धारित किया है। जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि राज्य बांस मिशन ने निजी क्षेत्र के इच्छुक लाभार्थियों से 30 सितंबर तक प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में बांस आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए 10 क्षेत्रों के पहचान की है। अधिकारी ने बताया कि पिछले वित्त वर्ष में राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र के लाभार्थियों की 16 इकाइयां मंजूर की थीं और उन्हें 2.03 करोड़ रुपये का अनुदान दिया था। उन्होंने कहा कि यह अनुदान प्रमुख रूप से बांस के ट्रीटमेंट तथा सीजनिंग प्लांट, बांस प्र-संस्करण केन्द्र एवं मूल्य संवर्धन इकाई, बांस कचरा प्रबंधन, अगरबत्ती इकाई, एक्टिवेटेड़ कार्बन प्रोडक्ट, बेम्बो बोर्ड/फ्लोर टाइल्स यूनिट और हाईटेक और बिग नर्सरी के प्रोजेक्ट पर दिया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि इन उद्योगों के मामलों में राज्य बांस मिशन द्वारा परियोजना तैयार करने के लिये मार्गदर्शन दिया जा सकेगा। राज्य बांस मिशन, संबंधित बैंक की सहमति के बाद उपलब्ध बजट सीमा में परियोजना को स्वीकृत करेगा और बैंक के माध्यम से हितग्राही को अनुदान राशि का भुगतान कराया जाएगा।

# स्टार्टअप और इनोवेशन को लिये मॉडर्न इंक्युबेटर डिक्सी नेक्ट-जेन के अभियान से जुड़ा

***■अंबेडकर सोशल इन्नोवेशन इंक्यूबेशन मिशन के अंतर्गत स्टार्टअप को मिलेगा बढ़ावा।***

***■सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की ओर से पहल की गयी है।***

***■कार्यक्रम में मध्यप्रदेश शासन के एम.एस.एम.ई मंत्रालय के मुख्य सचिव श्री पी.नरहरि मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।***

***■मॉडर्न ग्रुप ऑफ़ इंस्टीट्यूट्स के समूह निदेशक एवं मॉडर्न इंक्युबेटर के मुख्य सलाहकार डॉ. पुनीत द्विवेदी वक्ता के रूप में रहे आमंत्रित***

**इंदौर। एजेंसी**

डिक्सी नेक्स्ट जेन के द्वारा सामाजिक न्याय एवं उद्यमिता विषय पर आज एक वेबिनार का आयोजन किया गया जिसमें मध्यप्रदेश शासन के एम.एस.एम.ई मंत्रालय के मुख्य सचिव श्री पी.नरहरि मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बतादें कि 'अम्बेडकर सोशल इनोवेशन इनक्यूबेशन मिशन' सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित एक उत्कृष्ट पहल है, जो अनुसूचित जाति-जनजाति के युवाओं में टेक स्टार्ट-अप आईडिया और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा संचालित है। अभियान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के युवाओं के बीच निम्नलिखित योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने की परिकल्पना की गई है ताकि उन्हें एक स्थायी कैरियर पथ के रूप में नवाचार और उद्यमिता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। डीएनजी मध्य प्रदेश के लिए उद्यमिता पहल के तहत विभिन्न योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए आईएफसीआई वेंचर

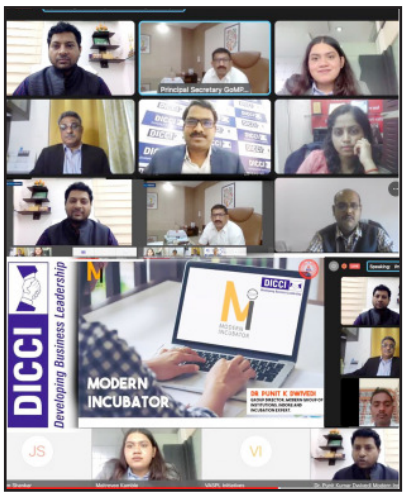


कैपिटल फंड और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से हमारी ऑनलाइन आउटरीच अभियान श्रृंखला के लिए एक भागीदार के रूप में मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के इंक्युबेटर टीबीआई, एआईसी, बिजनेस इनक्यूबेटर सम्मिलित हुये। जिसमें इंदौर के मॉडर्न ग्रुप ऑफ़ इंस्टीट्यूट्स द्वारा संचालित मॉडर्न इंक्युबेटर भी आमंत्रित रहा। मॉडर्न इंक्युबेटर के मुख्य सलाहकार ने वक्ता के रूप में मॉडर्न इंक्युबेटर द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में किये जा रहे नवाचारों की जानकारी दी एवं फ़ार्मा इंक्यूबेशन के क्षेत्र में अपार संभावनाओं के बारे में अपने विचार व्यक्त किये। ज्ञातव्य है कि इंदौर के मॉडर्न ग्रुप ऑफ़ इंस्टीट्यूट्स द्वारा संचालित एम.एस.एम.ई समर्थित मॉडर्न इंक्युबेटर इंदौर एवं आस-पास के क्षेत्रों में उद्यमिता एवं नवाचार हेतु डिक्सी नेक्स्ट जेन के साथ मिलकर अम्बेडकर सोशल इनोवेशन इनक्यूबेशन मिशन के अंतर्गत जागरूकता अभियान चलायेगा जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी कोष (वीसीएफएससी), अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना (सीईजीएसएससी) आदि प्रमुख हैं। संस्थाध्यक्ष डॉ. अनिल खरया एवं उपाध्यक्ष श्री शांतनु खरया ने मॉडर्न इंक्युबेटर की इस उपलब्धि पर बधाई दी।

# सरकार ने म्यांमा से 2.5 लाख टन उड़द के आयात के लिये प्रक्रिया तय की

**नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क**

सरकार ने चालू वित्त वर्ष में म्यांमा से 2.5 लाख टन उड़द और एक लाख टन तुअर दाल के आयात को लेकर सोमवार को प्रक्रिया तथा तौर-तरीके तय किये। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने कहा कि आयात केवल पांच बंदरगाहों... मुंबई, तुतीकोरिन, चेन्नई, कोलकाता और हजीरा... के जरिये करने की अनुमति होगी। आयात उत्पत्ति स्थल प्रमाणपत्र पेश करने पर निर्भर करेगा। दाल के आयात को लेकर भारत और म्यांमा के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए हैं। डीजीएफटी ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा है, ''समझौते के तहत म्यांमा से ढाई लाख टन उड़द और एक लाख टन तुअर दाल के आयात को लेकर प्रक्रियाएं/तौर-तरीके तय किये गये हैं।''

# डेयरी प्रॉडक्ट्स के नाम पर अब नहीं चलेगी धांधली

## केंद्र हुआ सख्त, राज्यों को दिया जांच का आदेश

**नई दिल्ली। एजेंसी**

डेयरी प्रॉडक्ट्स के नाम पर बेचे जाने वाले नॉन-डेयरी प्रॉडक्ट्स पर अब लगाम लगेगी। केंद्र ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए राज्यों को इस तरह के मामलों की जांच करने को कहा है। केंद्र को शिकायत मिली है कि कई फूड बिजनस ऑपरेटर्स (FBO) प्लांट बेस्ड बेवरेजेज और फूड प्रॉडक्ट्स को डेयरी प्रॉडक्ट्स बताकर बेच रहे हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आने वाले फूड रेग्युलेटर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने हाल में एक आदेश में राज्यों के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट्स से ऐसे एफबीओ की जांच और पहचान करने को कहा है जो डेयरी प्रॉडक्ट्स के नाम पर नॉन-डेयरी या प्लांट बेस्ट प्रॉडक्ट्स बेच रहे हैं। एफबीओ को अपने प्रॉडक्ट्स का लेबल ठीक करने और FSS (Food Products Standards and Food Additives) Regulation, 2011 के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

### 2 से 10 लाख रुपये का जुर्माना

सूत्रों के मुताबिक नियमों का पालन नहीं करने वाले फूड बिजनस ऑपरेटर्स पर 2 से 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। 2011 के कानून के मुताबिक किसी भी नॉन-डेयरी प्रॉडक्ट के लिए डेयरी शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ई-कॉमर्स फूड बिजनस ऑपरेटर्स के जरिए इस तरह के कई उत्पाद बेचे जा रहे हैं, इसलिए इएएंइ ने सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को इस तरह के उत्पादों को तुरंत लिस्ट से हटाने को कहा है। रेग्युलेटर ने साथ ही कहा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर लिस्टेड इस तरह के उत्पादों की भविष्य में बिक्री की अनुमति नहीं होनी चाहिए।

# डोर-टू-डोर वैक्सीनेशन का आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

## कहा- सही तो चल रहा है टीकाकरण

**नयी दिल्ली। एजेंसी**

देश में चल रहे कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने घर-घर जाकर टीकाकरण को लेकर आदेश देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि देश की विविध स्थितियों को देखते हुए घर-घर जाकर कोरोना का टीकाकरण करना संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल टीकाकरण सही तरीके से चल रहा है, ऐसे में हम मौजूदा टीकाकरण नीति को खत्म करने के लिए अलग से एक सामान्य आदेश पारित नहीं कर सकते।

सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगों और समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के लिए डोर-टू-डोर कोरोना वैक्सीन की मांग करने वाले वकीलों के निकाय की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने कहा कि टीकाकरण अभियान उचित प्रगति पर है और 60 प्रतिशत से अधिक आबादी को वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। पीठ ने याचिकाकर्ता 'यूथ बार एसोसिएशन' को अपने सुझावों के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने को कहा। पीठ ने कहा कि लद्दाख में स्थिति केरल से अलग है। उत्तर प्रदेश में स्थिति किसी भी अन्य राज्य से अलग है। शहरी क्षेत्रों में स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों से अलग है। इस विशाल देश में हर राज्य में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। ऐसे में आप पूरे देश के लिए एक आदेश चाहते हैं। टीकाकरण अभियान पहले से ही चल रहा है और 60 प्रतिशत से अधिक आबादी को पहली खुराक दी गई है। इस कठिनाई को समझना चाहिए। यह सरकार का मामला है और हम मौजूदा नीति को खत्म नहीं कर सकते।

शीर्ष अदालत ने एसोसिएशन की ओर से पेश हुए वकील बेबी सिंह से कहा कि इतने संवेदनहीन तरीके से याचिका दायर नहीं की जा सकती। याचिका में भारत सरकार और सभी राज्यों को समाज के कमजोर तबकों, विकलांग लोगों के लिए घर-घर जाकर कोविड-19 रोधी टीके लगाए जाने की व्यवस्था करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था, क्योंकि इन लोगों को कोविन पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पीठ ने कहा कि टीकाकरण कार्यक्रम पहले से ही चल रहा है और यह न्यायालय स्वतः संज्ञान लेकर स्थिति की निगरानी कर रही है। पीठ ने कहा कि देश की विविधता को देखते हुए सामान्य दिशा-निर्देश पारित करना संभव और व्यावहारिक नहीं है। पीठ ने कहा, ''किसी भी निर्देश को पारित करने से सरकार की मौजूदा टीकाकरण नीति प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

# डॉ रेड्डीज ने स्पुतनिक-वी वैक्सीन की पहली खुराक की आपूर्ति शुरू की

**हैदराबाद। आईपीटी नेटवर्क**

डॉ रेड्डीज लेबोरेटरीज ने मंगलवार को कहा कि उसने रूस की कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक- वी की पहली खुराक की आपूर्ति पूरे देश के साझेदार अस्पतालों में शुरू कर दी है। इससे पहले खबर आई थी कि पैनेसिया बायोटेक ने भारत में बिक्री के लिए उसके द्वारा विनिर्मित रूसी स्पुतनिक वी वैक्सीन के दूसरे घटक की पहली खेप की आपूर्ति की है। डॉ रेड्डीज ने इससे पहले रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष से आपूर्ति बाधाओं के बाद स्पुतनिक वी की पहली खुराक की आपूर्ति को टाल दिया था। डॉ रेड्डीज के प्रवक्ता ने कहा कि पहली खुराक की आपूर्ति के बाद बराबर मात्रा में दूसरी खुराक की आपूर्ति की जाएगी। कंपनी ने स्पुतनिक-वी टीके की उपलब्धता को लेकर लोगों को ताजा जानकारी देने के लिये वेबसाइट भी शुरू की है। इसमें शहरों, अस्पतालों की सूची होगी जहां टीका उपलब्ध होगा। यह जानकारी www.drreddys.com/sputnik-vaccine साइट पर उपलब्ध होगी। प्रवक्ता ने कहा कि ''जैसा कि हमारे भागीदार - आरडीआईएफ और पेनेसिया बायोटेक ने घोषणा की है पेनेसिया बायोटेक द्वारा विनिर्मित दूसरी खुराक के घटक की आपूर्ति अब शुरू हो गई है। डा. रेड्डीज ने पहली खुराक के घटक की देशभर में स्थित अपने भागीदार अस्पतालों को आपूर्ति शुरू कर दी है, इसके साथ ही इतनी ही मात्रा में दूसरी खुराक के घटक की भी आपूर्ति होगी।''

# ब्रिटेन में स्वास्थ्य, सामाजिक देखभाल खर्च के वित्त पोषण के लिये नया कर लगाने का प्रस्ताव

**लंदन। एजेंसी**

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने मंगलवार को नये कर का प्रस्ताव किया। इस नये कर से प्राप्त राशि का उपयोग कोविड-19 महामारी को देखते हुए स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल से जुड़े कार्यों में किया जायेगा। प्रस्ताव के तहत अगले साल अप्रैल से देशभर में 1.25 प्रतिशत स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल शुल्क के रूप में लिये जाएंगे। इसके तहत अनिवार्य राष्ट्रीय बीमा (एनआई) में करदाताओं के योगदान को बढ़ाया जाएगा। यह कदम जॉनसन के चुनावी घोषणापत्र के विपरीत है, जिसमें उन्होंने कर की दरों में वृद्धि नहीं करने की घोषणा की थी।हालांकि, उन्होंने अपने तथाकथित सामाजिक देखभाल पैकेज को राज्य-वित्त पोषित राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) के लिए 'सबसे बड़े कार्यक्रम' के रूप में बचाव किया। उन्होंने कहा कि महामारी ने घोषणापत्र की बातों के अनुसरण को मुश्किल बना दिया है। उन्होंने निचले सदन 'हाउस ऑफ कामन्स' में कहा, ''कंजरवेटिव पार्टी कर बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहती और मैं सदन के प्रति ईमानदार रहूंगा। मैं घोषणापत्र में जतायी गयी प्रतिबद्धताओं को तोड़ने की बात स्वीकार करता हूं...।'' जॉनसन ने कहा, ''लेकिन वैट्रश्विक महामारी किसी के घोषणापत्र में नहीं थी। मुझे लगता है कि इस देश के लोग समझते हैं... और वे देख सकते हैं कि इस सरकार ने काफी सारा कर्ज लिया है।'' इस कर प्रस्ताव पर संसद में इसी सप्ताह मतदान कराये जाने की योजना है। मंत्रिमंडल ने इसे मंगलवार को मंजूरी दी। कंजरवेटिव पार्टी के नेता प्रस्तावित नये कर का विरोध कर रहे हैं। शुल्क में 1.25 प्रतिशत की वृद्धि से शुरूआती वर्षों में 12 अरब पौंड जुटाये जाने की उम्मीद है। इसका उपयोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं से संबद्ध योजनाओं के वित्त पोषण में किया जाएगा।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।